

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

प्रेषित,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

सिंचाई अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 29 सितम्बर, 2016

विषय:- उत्तराखण्ड, विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम-2012 यथासंशोधित 2016 के अन्तर्गत उत्पादनरत् जल विद्युत परियोजनाओं से जलकर की वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-2869/II-1015-4(46)/2015, दिनांक 05.11.201, अधिसूचना सं0-2883/II-2015/01(50)/2011, दि0 07.11.15, अधिसूचना सं0-1439/II-2016/01(50)/2011, दि0 08.06.16 (छायाप्रतियाँ संलग्न) एवं उत्तराखण्ड, विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम-2012 यथासंशोधित 2016 (www.uttarakhandirrigation.com पर उपलब्ध) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में समस्त निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का पंजीकरण किया जाना एवं 5 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता की उत्पादनरत् जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये जल की मात्रा पर जलकर अधिरोपित किया जाना एवं इसकी वसूली करना प्राविधानित है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम 2012 की धारा 29 के अनुसार "आयोग या कोई अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे के पद का न हो, ऐसे किसी स्थान पर भवन में प्रवेश कर सकता है, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से सम्बन्धित दस्तावेज पाया जा सकता है तथा ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिग्रहित कर सकता है या भारतीय दंड संहिता के प्राविधानों के अधीन उसकी प्रतियां निकाल सकता है, प्राविधान निहित है, जिसके अन्तर्गत अधिसूचना सं0-1439/II-2016/01(50)2011, दिनांक 08.06.2016 उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग के 27 अधिशासी अभियन्ताओं को तदनुसार कार्यवाही हेतु अधिकृत गया है।

उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग द्वारा अद्यतन राज्य में 5 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता की 23 उत्पादनरत् जल विद्युत परियोजनायें चिन्हित की गई हैं। इन योजनाओं पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार जलकर निर्धारण हेतु विद्युत उत्पादन में प्रयोग किये गये जल की मात्रा एवं अन्य वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित परियोजना संचालकों/स्वामियों से सिंचाई विभाग के स्थानीय अधिकारियों/उच्चाधिकारियों द्वारा निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है। यू0जे0वी0एन0 लिमिटेड के स्वामित्व में स्थित 12 जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त अधिकांश परियोजनाओं के स्वामियों/संचालकों द्वारा या तो सूचनायें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं अथवा इस दिशा में पर्याप्त सहयोग नहीं किया जा रहा है। जैसाकि आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों हेतु धन की आवश्यकता एवं राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्व बढ़ोत्तरी के प्रयासों हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जलकर की मद में लगभग रु0 350 करोड़ वार्षिक की राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित/प्रस्तावित किया गया है।

अतः उल्लिखित पत्रों/अधिसूचनाओं की छायाप्रतियाँ एवं उल्लिखित 23 विद्युत उत्पादनरत् परियोजनाओं की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का समुचित प्रयोग कर जलकर पंजीकरण एवं जलकर प्राप्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग द्वारा वांछित समस्त सूचनायें उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08.06.2016 द्वारा नामित सिंचाई विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध करवाने एवं सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को पूर्व में प्रेषित 07.11.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के जलकर के बीजकों की वसूली करवाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव

पृ०सं / 2016- II -01(50) / 2011तददिनांक

प्रतिलिपि उपरोक्तानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, देहरादून ।
5. नोडल अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं अवस्थापना मण्डल, देहरादून ।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिषद, देहरादून ।

आज्ञा से

(किशन नाथ)

अपर सचिव